vinetur

दक्षिण अफ्रीकी शोधकर्ताओं ने बीयर पर तीन-स्तरीय कर का प्रस्ताव दिया, जिससे शुद्ध अल्कोहल की खपत 14.3% घट सकती है

मॉडल में राष्ट्रीय कोषागार से 3.5% और 4.5% ABV श्रेणियों के आधार पर बीयर पर कर लगाने की अपील की गई है और माना गया है कि ब्रुअर उत्पादों की रीफॉर्म्युलेशन करेंगे

शुक्रवार, 20 नवंबर 2026



दक्षिण अफ्रीकी शोधकर्ताओं के एक समूह ने बीयर पर तीन-स्तरीय कर का प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि कम अल्कोहल वाली बीयर बनाने के लिए ब्रुअरों को प्रोत्साहित करके बीयर से होने वाली शुद्ध अल्कोहल की खपत अनुमानित 14.3% तक घटाई जा सकती है।

यह प्रस्ताव गुरुवार, 19 नवंबर को Polity में प्रकाशित एक विश्लेषण में पेश किया गया था, जिसका शीर्षक था 'बीयर करों में बदलाव कैसे जानें बचा सकता है'। Polity ने कहा कि लेख में यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन की रिसर्च यूनिट ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ एक्साइजबल प्रोडक्ट्स (REEP) से जुड़े शोधकर्ताओं का काम प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्ताव

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय कोषागार के लिए है, जो बजट और कर नीति का जिम्मा संभालता है।

शोधकर्ता इसे ऐसा कर परिवर्तन नहीं बता रहे हैं जिसे लागू कर दिया गया हो। वे यह मॉडल बना रहे हैं कि यदि निर्माता कर प्रोत्साहनों का पूरा लाभ उठाते हुए अपने उत्पादों की रीफॉर्म्युलेशन करें, तो आबकारी कर की अलग संरचना दक्षिण अफ्रीका में बिकने वाली बीयर की अल्कोहल मात्रा को किस तरह बदल सकती है।

यह अंतर महत्वपूर्ण है। अनुमानित 14.3% की कमी का संबंध बीयर से सेवन की गई शुद्ध अल्कोहल से है, न कि बिकने वाली बीयर की कुल मात्रा में उतनी ही गिरावट से। उदाहरण के लिए, कोई ब्रुअर लगभग उतनी ही मात्रा में बीयर बेचना जारी रख सकता है, लेकिन कुछ ब्रांडों की अल्कोहल मात्रा घटाकर उन्हें कम कर-दर वाली श्रेणी में ला सकता है।

तीन-स्तरीय मॉडल के तहत बीयर पर अल्कोहल बाय वॉल्यूम (ABV) के आधार पर अलग-अलग दरों से कर लगाया जाएगा। प्रस्ताव में 3.5% और 4.5% की सीमाएं दी गई हैं, जबकि विश्लेषण का व्यापक दायरा 0.5% ABV से शुरू होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य कम अल्कोहल वाली बीयर के उत्पादन और विपणन के लिए अधिक स्पष्ट वित्तीय प्रोत्साहन देना है।

विश्लेषण के अनुसार, ऐसी व्यवस्था का असर कर राजस्व से आगे भी हो सकता है। इससे रेसिपी संबंधी फैसले, उत्पाद पोर्टफोलियो, पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण और बाजार में बीयर की स्थिति प्रभावित हो सकती है। कोई ब्रांड यदि तय सीमा से थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए, तो उस पर अलग कर लागू हो सकता है। इससे उत्पादकों को अल्कोहल की मात्रा थोड़ी घटाने का कारण मिल सकता है, भले ही व्यावसायिक रूप से यह छोटा बदलाव हो।

शोधकर्ताओं ने चार-स्तरीय व्यवस्था का मॉडल भी बनाया। इस विकल्प में बीयर से सेवन की गई शुद्ध अल्कोहल में अनुमानित कमी बढ़कर 15.7% हो जाती है। यानी मॉडल के मुताबिक चार-स्तरीय व्यवस्था का असर तीन-स्तरीय विकल्प से अधिक है, लेकिन अंतर केवल 1.4 प्रतिशत अंक का है। इसलिए सिमुलेशन में तीन-स्तरीय प्रस्ताव कुछ कम सख्त है, फिर भी इससे बीयर से होने वाली अल्कोहल खपत में उल्लेखनीय कमी दिखाई देती है।

19 नवंबर के प्रकाशन में बीयर की बिक्री के नए आंकड़े पेश नहीं किए गए। इसमें पहले के शोध के निष्कर्षों का सार दिया गया और अगस्त 2026 में प्रकाशित एक पद्धतिगत विस्तार को शामिल किया गया। इन आंकड़ों को नीति मॉडल से निकले सिमुलेशन नतीजों के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि उपभोक्ता व्यवहार, ब्रुअरों के उत्पादन या मासिक बाजार प्रदर्शन में बदलाव की नई सांख्यिकीय रिपोर्ट के तौर पर।

आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, इसकी यह एक महत्वपूर्ण सीमा है। अध्ययन में बीयर की बिक्री के लीटर में पूर्ण बदलाव नहीं बताया गया है। इसमें महीने-दर-महीने या साल-दर-साल बिक्री की तुलना भी नहीं है। 19 नवंबर के लेख में उद्धृत सामग्री में कोई मौद्रिक अनुमान नहीं दिया गया है ; इसमें केवल अल्कोहल खपत और अल्कोहल की मात्रा से जुड़े प्रतिशत बदलाव हैं।

यह प्रस्ताव ऐसे शोध क्षेत्र से निकला है जो तथाकथित आबकारी-कर योग्य उत्पादों का अध्ययन करता है। इनमें अल्कोहल, तंबाकू और मीठे पेय शामिल हैं, जिन पर सरकारें अक्सर राजस्व जुटाने के साथ-साथ व्यवहार को प्रभावित करने के लिए भी कर नीति का इस्तेमाल करती हैं। इस मामले में ध्यान इस बात पर है कि क्या कर व्यवस्था व्यापक रूप से कर दरें बढ़ाए बिना बीयर बाजार को अधिक अल्कोहल वाली बीयर से दूर कर सकती है।

अल्कोहल की मात्रा पर अधिक सटीक रूप से आधारित कर, ऐसी समान कर व्यवस्था से अलग होगा जिसमें बीयर की कई श्रेणियों पर लगभग एक जैसा कर लगाया जाता है। सिद्धांततः, कर का संबंध अल्कोहल की मात्रा से जितना अधिक निकट होगा, उत्पादकों पर ABV घटाने का दबाव उतना ही बढ़ेगा—बशर्ते उपभोक्ता उस उत्पाद को स्वीकार करें। इसमें मौजूदा बीयर की रीफॉर्म्युलेशन, कम अल्कोहल वाले नए विकल्प पेश करना या कम कर वाली श्रेणियों के उत्पादों को तरजीह देने के लिए विपणन मिश्रण बदलना शामिल हो सकता है।

विश्लेषण के अनुसार, कर व्यवस्था की बनावट मायने रखती है, क्योंकि यह पूरी आपूर्ति शृंखला में प्रोत्साहनों को बदल सकती है। ब्रुअर अपेक्षित लाभ के हिसाब से फैसले लेते हैं। खुदरा विक्रेता कीमतों और उपभोक्ता मांग के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। उपभोक्ता इस बात से प्रभावित होते हैं कि उनके लिए क्या उपलब्ध है और उत्पादों का विपणन किस तरह किया जाता है। कम अल्कोहल वाली बीयर को अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक बनाकर, स्तरीय व्यवस्था इन तीनों को प्रभावित करने का प्रयास करती है।

हालांकि, यह मॉडल एक मजबूत मान्यता पर आधारित है। REEP के बताए परिदृश्यों में माना गया है कि कर प्रोत्साहन के जवाब में उत्पादक अपने उत्पादों की पूरी तरह रीफॉर्म्युलेशन करेंगे। वास्तविक नतीजे अलग हो सकते हैं—यदि कंपनियां रेसिपी बदलने का फैसला न करें, उपभोक्ता लोकप्रिय ब्रांडों के कम अल्कोहल वाले संस्करणों को न अपनाएं या प्रतिस्पर्धा के चलते कंपनियां उत्पादों को नए सिरे से तैयार करने के बजाय कर बदलाव का कुछ बोझ खुद उठाएं।

इन सीमाओं को देखते हुए, इस प्रस्ताव को पूर्वानुमान के बजाय एक नीतिगत विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। यह बताता है कि कुछ मान्यताओं के तहत क्या हो सकता है, न कि दक्षिण अफ्रीका के बीयर बाजार में निश्चित रूप से क्या होगा।

फिर भी, यह अध्ययन राष्ट्रीय कोषागार को इस बात पर विचार करने के लिए एक ठोस ढांचा देता है कि आबकारी नीति जनस्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। मॉडल का मुख्य संदेश है कि बीयर कर की संरचना—सिर्फ उसकी कुल दर नहीं—इस बात को प्रभावित कर सकती है कि उपभोक्ता अंततः कितनी अल्कोहल पीते हैं।

ब्रुअरों के लिए इससे कर नीति उत्पाद विकास का मुद्दा बन सकती है। नीति-निर्माताओं के लिए यह आबकारी कर की बनावट को राजस्व संग्रह से आगे असर डालने वाले औजार के रूप में प्रस्तुत करती है। और बाजार के लिए, यह संकेत देता है कि 3.5% और 4.5% जैसी छोटी ABV सीमाएं भी कारोबारी फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं, यदि उनसे कर में सार्थक अंतर जुड़ा हो।